

# व्यूज टुडे

## भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने "वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSFI): 2025-30" जारी की

इस रणनीति को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप-समिति ने अनुमोदित किया है। यह रणनीति संपूर्ण देश में विश्वसनीय रूप से सुदूर क्षेत्रों तक वित्तीय पहुंच एवं वित्तीय सेवाओं के प्रभावी उपयोग को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSFI): 2025-30 के बारे में

- ▶ यह भारत में वित्तीय समावेशन को बेहतर बनाने के लिए पांच प्रमुख लक्ष्यों (पंच-ज्योति) की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 47 विशिष्ट कार्य बिंदुओं का समर्थन प्राप्त है।
- ▶ पंच-ज्योति:
  - ⊕ परिवारों एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तीय सुरक्षा और संरक्षा प्राप्त करने हेतु न्यायसंगत, उपयुक्त तथा किफायती वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता व उपयोग में सुधार करना।
  - ⊕ महिला-नेतृत्व वाले वित्तीय समावेशन के लिए लैंगिक-संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना। साथ ही, परिवारों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने तथा विशेष रूप से सेवाओं से वंचित व सुभेद्य वर्गों के लिए अलग-अलग तरीके की रणनीतियां बनाना।
  - ⊕ आजीविका, कौशल विकास और समर्थन तंत्र एवं इसके संपर्कों का वित्तीय समावेशन के साथ समन्वय सुनिश्चित करना।
  - ⊕ वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में वित्तीय शिक्षा का लाभ उठाना।
  - ⊕ ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण उपायों की गुणवत्ता को मजबूत करना।

वित्तीय समावेशन (FI) और भारत में इसकी वृद्धि

- ▶ विश्व बैंक के अनुसार, वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि व्यक्तियों और व्यवसायों को ऐसे उपयोगी एवं किफायती वित्तीय उत्पादों व सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो, जो उनकी आवश्यकताओं को जिम्मेदारीपूर्वक और सतत रूप से पूरा कर सकें।
- ▶ RBI FI-सूचकांक 2021 से 24.3% बढ़कर 2025 में 67 हो गया है।
  - ⊕ FI-सूचकांक बैंकिंग, निवेश, बीमा, पेंशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश में वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।

वित्तीय समावेशन के लिए अन्य सरकारी पहलें

- ▶ वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति (NSFI 2019-2024): यह वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है।
- ▶ प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) (2014): इसने 56 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलने की सुविधा प्रदान की है।
- ▶ डिजिटल इंडिया: इसने डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार किया है।
- ▶ जैम ट्रिनिटी (JAM Trinity) (जन धन-आधार-मोबाइल): इसने मोबाइल फ़ोन के बढ़ते उपयोग का लाभ उठाने के लिए आवश्यक डिजिटल पब्लिक गुड्स अवसंरचना प्रदान की है।

## विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मोटापे के उपचार में GLP-1 दवाओं के उपयोग पर वैश्विक दिशा-निर्देश जारी किए

WHO ने मोटापे के लिए GLP-1 उपचारों की सशर्त अनुमति दी है। WHO के व्यापक दिशा-निर्देश में स्वस्थ आहार का सेवन, शारीरिक सक्रियता बढ़ाना, स्वास्थ्य पेशेवर की सहायता लेना जैसे व्यापक दृष्टिकोण शामिल हैं।

- ▶ ये दिशा-निर्देश वयस्कों में मोटापे के दीर्घकालिक उपचार में उपयोग होने वाली तीन GLP-1 दवाओं के लिए विशेष सिफारिशें प्रदान करते हैं। ये तीन दवाइयां हैं: लिराग्लूटाइड, सेमाग्लूटाइड और टिरेज़ेपाटाइड।

GLP-1 दवाओं या GLP-1 एगोनिस्ट के बारे में

- ▶ ये दवाओं का एक समूह है जो ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1 (GLP-1) नामक हार्मोन की क्रियाविधि की नकल करते हैं। यह हार्मोन भोजन के बाद प्राकृतिक रूप से आंत से उत्सर्जित होता है।
- ▶ GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट आवश्यकता पड़ने पर इंसुलिन बढ़ाकर और ग्लूकागन कम करके रक्त शर्करा (Blood sugar) को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
- ▶ ये दवाइयां पाचन को धीमा करती हैं और भूख कम करती हैं। इससे बेहतर भोजन तृप्ति का एहसास होता है और इससे वजन घटाने में सहायता मिलती है।
- ▶ इस उपचार का उपयोग मुख्य रूप से टाइप-2 मधुमेह और मोटापा कम करने के लिए किया जाता है।

मोटापे के बारे में एवं इसका वर्तमान प्रसार

- ▶ मोटापा (Obesity) अत्यधिक वसा संचय (Fat deposits) के कारण होता है। इससे टाइप-2 मधुमेह, हृदय रोग जैसे विकारों का खतरा बढ़ जाता है।
- ▶ वयस्कों में बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 30 या उससे अधिक होने को मोटापा माना जाता है।
  - ⊕ BMI किसी व्यक्ति के वजन (किलोग्राम में) को उसकी लंबाई (वर्ग मीटर में) से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। इसे किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर (kg/m<sup>2</sup>) में व्यक्त किया जाता है।
- ▶ विश्व के 1 बिलियन से अधिक लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। 2024 में वैश्विक स्तर पर मोटापे की वजह से 37 लाख लोगों की मौत हो गई।
  - ⊕ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5/ NFHS-5 (2019-21) के अनुसार, भारत में 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं।

## उच्चतम न्यायालय ने 'डिजिटल अरेस्ट' के मामलों की व्यापक जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिए

### डिजिटल अरेस्ट से संबंधित मुख्य निर्देश

- उच्चतम न्यायालय ने CBI को डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ियों के उद्देश्य से खोले गए बैंक खातों के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत बैंकों की भूमिका की जांच करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है।
- पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और हरियाणा सहित सभी राज्यों को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम की धारा 6 के तहत CBI को अपनी सहमति देने का निर्देश दिया गया है। इससे CBI संपूर्ण देश में जांच कर सकेगी।
- न्यायालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भी पक्षकार बनाया है तथा धोखाधड़ी वाले खातों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले AI व मशीन लर्निंग उपकरणों को समझाने में उसकी सहायता मांगी है।
- सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं को जांचकर्ताओं के साथ पूर्ण सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया है।

### डिजिटल अरेस्ट क्या है?

- डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी है। इसके तहत धोखाधड़ी करने वाला फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से स्वयं को CBI, पुलिस, ED (प्रवर्तन निदेशालय) जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकारी बताता है और पीड़ितों पर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का झूठा आरोप लगाकर उनसे धन की मांग करता है।
- वर्ष 2024 की पहली तिमाही के दौरान 'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी की घटनाओं में भारतीयों ने ₹120 करोड़ से अधिक गँवाए हैं।



### डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए सरकारी पहलें

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): इसे देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया है।
- साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (CFMC): इसे I4C में स्थापित किया गया है। इसमें प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यवर्तियों, भुगतान संग्राहकों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए मिलकर कार्य करते हैं।
- समन्वय प्लेटफॉर्म (संयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली): यह विभिन्न राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों व अपराधियों के अंतरराज्यीय संपर्कों के आधार पर विश्लेषण प्रदान करता है।
- <https://cybercrime.gov.in> पर 'रिपोर्ट और संदिग्ध की जांच करें': केंद्र सरकार ने यह सुविधा शुरू की है, जो नागरिकों को साइबर अपराधियों के पहचानकर्ताओं की I4C रिपोर्टिटी के लिए सर्च ऑप्शन प्रदान करती है।

## केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने विश्व एड्स दिवस 2025 मनाया

वर्ष 1992 में अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाता रहा है। यह संगठन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

- वैसे विश्व एड्स दिवस वर्ष 1988 से मनाया जाता रहा है।
- ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस (HIV) और एड्स के बारे में
- HIV वायरस एक रेट्रोवायरस है। यह CD4 प्रतिरक्षी कोशिकाओं को निशाना बनाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है।
  - CD4 कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार हैं। यह शरीर को संक्रमण से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- रेट्रोवायरस वह वायरस है जो अपने जीनोमिक पदार्थ के रूप में RNA का उपयोग करता है। रेट्रोवायरस से संक्रमण होने पर, कोशिका रेट्रोवायरस RNA को DNA में परिवर्तित करती है। इसे बाद में होस्ट कोशिका के DNA में डाल दिया जाता है।
  - इसके बाद कोशिका और अधिक रेट्रोवायरस सृजित करती है, जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं।
- HIV का उपचार: प्रारंभिक जांच और नियमित एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) वायरल लोड यानी वायरस की संख्या को कम करती है और संक्रमण के प्रसार को धीमा करती है।
- संक्रमण के तरीके: असुरक्षित यौन संबंध, एक ही सुई को कई लोगों में इस्तेमाल करना, संक्रमित रक्त चढ़ाने पर, संक्रमित मां से बच्चे में संक्रमण।
- एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम (AIDS), HIV संक्रमण का सबसे उन्नत (एडवांस्ड) चरण है।

### भारत में HIV प्रसार का वर्तमान परिदृश्य

- भारत में 25 लाख से अधिक व्यक्ति HIV संक्रमित रूप में जीवन यापन कर रहे हैं।
  - भारत में केवल 0.20% वयस्क आबादी HIV संक्रमित है। यह 0.7% के वैश्विक औसत से काफी कम है।
- संक्रमण के प्रसार की घटती प्रवृत्तियाँ (2010-2024): राष्ट्रीय स्तर पर, वार्षिक रूप से HIV संक्रमण के नए मामले में 48.7% की कमी और AIDS-से होने वाली मौतों में 81.4% की कमी दर्ज की गई है।

### HIV/एड्स से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय एड्स और यौन-संचारित बीमारी (STD) नियंत्रण कार्यक्रम (NACP) फेज-V: यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसका लक्ष्य 2030 तक एड्स को लोक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना है।
- भारत ने एड्स को समाप्त करने के लिए 90-90-90 लक्ष्य अपनाया। बाद में, यह लक्ष्य बढ़ाकर 95-95-95 कर दिया गया। 95-95-95 लक्ष्य में शामिल हैं:
  - HIV से संक्रमित 95% लोगों को अपने संक्रमण के बारे में पता होना,
  - 95% निदान किए गए लोगों द्वारा नियमित रूप से एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) लेना, और
  - एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी ले रहे 95% मरीजों में HIV वायरस की संख्या (वायरल लोड) कम होना।
- अन्य कदम: मिशन सम्पर्क, HIV/AIDS (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 आदि।

## संसदीय समिति ने उर्वरक खपत में वृद्धि के कारण कठोर नीतियों का आग्रह किया

रासायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति को उजागर करती है। साथ ही, उर्वरकों के दुरुपयोग और आयात निर्भरता पर चिंताएं भी व्यक्त करती है।

चिंताएं/टिप्पणी	सिफारिशें
<b>घरेलू उत्पादन और क्षमता वृद्धि</b>	
<b>वर्तमान स्थिति:</b> भारत की उर्वरक खपत 2024-25 में 708 LMT (लाख मीट्रिक टन) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। इसके विपरीत, घरेलू उत्पादन यूरिया के लिए 307 LMT और फॉस्फोरस (P) व पोटाश (K) के लिए 211.21 LMT पर अपर्याप्त रहा। इससे भू-राजनीतिक आघातों के प्रति सुभेद्यता बढ़ गई है।	NIP-2012 व NUP-2015 के माध्यम से यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देने और राजकोषीय एवं कर प्रोत्साहनों के माध्यम से P&K क्षमता का विस्तार करने के लिए एक समयबद्ध रणनीति तैयार करनी चाहिए। इस हेतु एक उच्च-स्तरीय कार्य बल का गठन करना चाहिए। • NIP: नई निवेश नीति • NUP: नई यूरिया नीति
<b>पुरानी होती जा रही अवसंरचना:</b> 33 यूरिया संयंत्रों में से 27 संयंत्र 25+ वर्ष पुराने हैं और 7 संयंत्र 50+ वर्ष पुराने हैं। इससे उच्च परिचालन और रखरखाव लागत आती है।	अत्याधुनिक ऊर्जा-दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए एक विशेष कार्य बल गठित करना चाहिए।
<b>आयात निर्भरता कम करना और कच्चे माल को सुरक्षित करना</b>	
भारत की फॉस्फेट के लिए 95% और पोटाश के लिए 100% आयात पर निर्भरता है।	संसाधन-समृद्ध देशों के साथ दीर्घकालिक समझौते और वैश्विक संयुक्त उद्यम संपन्न करने चाहिए।
प्रौद्योगिकी और संयंत्र लाइसेंसिंग के लिए विदेशी लाइसेंसदाताओं (नीदरलैंड, अमेरिका, इटली, जापान आदि) पर निर्भरता।	मजबूत अनुसंधान एवं विकास (R&D) वित्त-पोषण द्वारा समर्थित एक उच्च-अधिकार प्राप्त कार्य बल के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए।
निम्न-श्रेणी के फॉस्फेट अयस्क और गहराई में भंडारित पोटाश भंडार।	खान और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 2023 के तहत "महत्वपूर्ण व रणनीतिक खनिज" (Critical & Strategic Minerals) दर्जे का लाभ उठाने हुए, कच्चे माल के घरेलू अन्वेषण व खनन के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
<b>विकल्पों को बढ़ावा देना और कदाचारों पर अंकुश लगाना</b>	
नैनो उर्वरक उपयोग के लिए अपर्याप्त ड्रोन।	बड़े पैमाने पर नैनो उर्वरक उपयोग का समर्थन करने के लिए ड्रोन हेतु PLI योजना (उत्पादन-से संबद्ध प्रोत्साहन योजना) शुरू करनी चाहिए।
आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होने के बावजूद कालाबाजारी/ दुरुपयोग जारी रहना।	कठोर प्रवर्तन प्रोटोकॉल लागू करना चाहिए। साथ ही, एक राष्ट्रव्यापी प्रयोगशाला नेटवर्क और शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।
रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित उपयोग, जिससे मृदा का निम्नीकरण और पोषक तत्वों की कमी होती है।	संतुलित उर्वरक उपयोग, फसल चक्रण, जैविक आदान और जैविक/ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए।

## अन्य सुर्खियां

### GIRG फ्रेमवर्क

भारत सरकार ने देश में सुधारों व विकास को गति देने हेतु सुधारों और संवृद्धि के लिए वैश्विक सूचकांक (GIRG) पहल शुरू की।

सुधारों और संवृद्धि के लिए वैश्विक सूचकांक (GIRG) फ्रेमवर्क के बारे में

- उद्देश्य: यह चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों पर भारत के प्रदर्शन की निगरानी करेगा। इससे कमियों की पहचान की जा सकेगी और साक्ष्य-आधारित सुधारों का मार्गदर्शन किया जा सकेगा।
- कवरेज: यह चार व्यापक विषयवस्तुओं (अर्थव्यवस्था, विकास, शासन और उद्योग) से संबंधित 26 वैश्विक सूचकांकों पर नजर रखेगा। ये सूचकांक 16 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं।
- कार्यान्वयन: 17 नोडल मंत्रालयों को विशिष्ट सूचकांक सौंपे गए हैं।
  - ⊕ नीति आयोग का विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) डेटा गुणवत्ता की जांच, कार्यप्रणाली की समीक्षा तथा सुधार कार्यान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाएगा।
- महत्त्व:
  - ⊕ यह पारदर्शिता बढ़ाएगा;
  - ⊕ नीति निर्माण को मजबूत करेगा;
  - ⊕ भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देगा; और
  - ⊕ सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद का समर्थन करेगा।

### बहुविवाह निषेध कानून

असम विधानसभा ने बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 पारित किया।

- इस विधेयक में दूसरी शादी करने पर 10 साल तक की कैद सहित कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।

बहुविवाह के बारे में

- इसका अर्थ है विवाह की एक ऐसी व्यवस्था, जिसमें एक व्यक्ति के एक से अधिक जीवनसाथी होते हैं।
- यह दो प्रकार का हो सकता है:
  - ⊕ बहुपत्नीत्व (Polygyny): इसमें एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है।
  - ⊕ बहुपतित्व (Polyandry): इसमें एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है।
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में द्विविवाह के लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82 पति या पत्नी के जीवनकाल में दोबारा शादी करने से संबंधित है। इसके लिए सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।

## संचार साथी

दूरसंचार विभाग (DoT) ने स्मार्टफोन निर्माताओं को नए उपकरणों में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने का आदेश दिया।

संचार साथी मोबाइल ऐप के बारे में

- इसे पारदर्शी और सुरक्षित मोबाइल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2025 में लॉन्च किया गया था।
- मुख्य विशेषताएं:
  - ⊕ चक्र: यह उपयोगकर्ताओं को कॉल, SMS या व्हाट्सएप पर प्राप्त धोखाधड़ी के संदेहास्पद संचार को रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि KYC के एक्सपायर होने या बैंक खाते का अपडेट होने का झांसा देना।
  - ⊕ IMEI ट्रैकिंग और ब्लॉकिंग: भारत में कहीं भी खोए या चोरी हुए फोन को ट्रैक व ब्लॉक करने की अनुमति देता है।
  - ⊕ अपने मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता जानें: यह सत्यापित करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है कि खरीदा गया मोबाइल उपकरण असली है या नहीं।
  - ⊕ भारतीय नंबरों से अंतर्राष्ट्रीय कॉल की रिपोर्टिंग: नागरिकों को +91 (कंटी कोड के बाद 10 अंक) से शुरू होने वाले नंबरों से घरेलू कॉल के रूप में छद्म अंतर्राष्ट्रीय कॉल की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है।
  - ⊕ अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता को जानें: उपयोगकर्ताओं को पिन कोड, पता या ISP नाम दर्ज करके पूरे भारत में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के विवरण की जांच करने की सुविधा देता है।

## GPS स्फूफिंग

नागर विमानन मंत्रालय ने दिल्ली और कई अन्य प्रमुख हवाई अड्डों पर GPS स्फूफिंग की पुष्टि की।

GPS स्फूफिंग के बारे में

- इसे GPS सिमुलेशन भी कहा जाता है। यह भ्रामक GPS सिग्नल प्रसारित करके GPS रिसेवर में हेरफेर या उसे धोखा देने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- यह GPS रिसेवर को यह विश्वास दिलाकर गुमराह करता है कि लोकेशन किसी और जगह की है। इसके परिणामस्वरूप, ड्रिवाइस गलत लोकेशन डेटा प्रदान करता है।
- इस प्रकार का साइबर हमला GPS डेटा की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। GPS डेटा नेविगेशन से लेकर टाइम सिंक्रोनाइजेशन आदि तक के विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है।

## ब्रह्मोस मिसाइल

भारतीय थल सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक लड़ाकू प्रक्षेपण किया।

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में

- यह दो-चरणीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके पहले चरण में ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट इंजन है।
- इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक सीमित है।
- इसकी क्रूजिंग ऊंचाई 15 किमी तक और टर्मिनल ऊंचाई 5 मीटर तक हो सकती है।
- यह 200 किलोग्राम तक के पारंपरिक वारहेड्स ले जा सकती है।
- विशेषताएं:
  - ⊕ सतह पर हमला करने की और पोत-रोधी क्षमताओं से युक्त;
  - ⊕ दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर संचालित होती है;
  - ⊕ बड़ा संलग्न आवरण;
  - ⊕ परिवहन-सह-प्रक्षेपण कनस्टर;
  - ⊕ न्यूनतम तैनाती समय आदि।

## हेरॉन एमके-II

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत इजरायल से अतिरिक्त हेरॉन एमके-II ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है। साथ ही, इसके भारत में ही निर्माण के लिए वार्ता भी चल रही है।

हेरॉन एमके-II के बारे में

- निर्माता: इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI)।
- श्रेणी: मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंजॉयर्स (MALE) मानव रहित हवाई वाहन (UAV) है। इसका उपयोग खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने और टोही कार्यों के लिए किया जाता है।
- उड़ान क्षमता: 35,000 फीट की ऊंचाई तक और 150 नॉट की गति से उड़ सकता है। साथ ही, लगातार 45 घंटे तक हवा में उड़ान भरे (Endurance) रह सकता है।
- क्षमताएं: उन्नत सेंसर, संचार आसूचना पैकेज और उपग्रह संचार सहायता से युक्त है। इन विशेषताओं के साथ यह लंबी दूरी के और लाइन ऑफ साइट से परे मिशनों को सक्षम बनाता है।

## अभ्यास एकुवेरिन

अभ्यास एकुवेरिन का 14वां संस्करण केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जा रहा है।

अभ्यास एकुवेरिन के बारे में

- यह भारतीय थल सेना और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- उत्पत्ति: धिवेही भाषा में “एकुवेरिन” का अर्थ “मिल” होता है। यह अभ्यास 2009 में शुरू हुआ था। इसका आयोजन भारत और मालदीव में बारी-बारी से किया जाता है।
- मुख्य उद्देश्य:
  - ⊕ उग्रवाद और आतंकवाद-रोधी अभियानों में आपसी समन्वय को बढ़ाना;
  - ⊕ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान संयुक्त रूप से संचालित करना; तथा
  - ⊕ अर्ध-शहरी, जंगली एवं तटीय इलाकों में अभियानों का अभ्यास करना।

## प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (PAHAL/ PAHAL) योजना

पहल (PAHAL) या एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना दक्षता, पारदर्शिता और उपभोक्ता-केंद्रित सुधार प्रदान करती है।

पहल (PAHAL) योजना के बारे में

- प्रारंभ: 2013 में।
- मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
- उद्देश्य:
  - ⊕ यह सुनिश्चित करना कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी वितरण और सब्सिडी अंतरण कुशल, पारदर्शी व समावेशी हो।
  - ⊕ सब्सिडी वाले एलपीजी के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाना।
- प्रक्रिया: सभी घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक समान खुदरा विक्रय मूल्य (RSP) पर बेचे जाते हैं। एलपीजी उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है।

## ₹ मसाला बॉण्ड

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल अवसंरचना निवेश कोष बोर्ड (KIIFB) द्वारा जारी ‘मसाला बॉण्ड’ की जांच की।

मसाला बॉण्ड क्या है?

- मसाला बॉण्ड रुपये-मूल्यवर्ग वाले बॉण्ड्स होते हैं। इन्हें भारतीय कंपनियां धन जुटाने के लिए विदेशी खरीदारों हेतु जारी करती हैं।
- इन्हें भारत में 2014 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने प्रस्तुत किया था।
- पालता: वित्तीय कार्यवाही कार्य बल (FATF) के अनुपालक क्षेत्राधिकार वाला कोई भी निवेशक निवेश करने के लिए पाल होता है।
- लाभ: मसाला बॉण्ड्स जारीकर्ताओं को मुद्रा विनिमय से जुड़े जोखिम से बचाने और इन बॉण्ड्स को खरीदने वाले निवेशकों पर मुद्रा जोखिम स्थानांतरित करने का एक प्रयास है।